इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 16, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. 27144-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ञ) में, शब्द ''भाण्डागारिक'' का लोप किया जाए.

धारा ३१ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, शब्द ''भाण्डागारिक'' का लोप किया जाए.

धारा ३८ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) मण्डी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियां जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएंगी.''.

धारा ४३ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४३ में, उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(७) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन तथा अन्य राशियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएंगी.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुभव करने पर कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) के कतिपय उपबंधों को, मण्डी समिति में कारबार करने को सुकर बनाने, आधुनिक बनाने तथा सरल बनाने की दृष्टि से, संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, कृषि-उपज के विपणन तथा विनियमन के संबंध में हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए अधिनियम के कतिपय उपबंधों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. यह विधेयक, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करता है:—

(एक) **अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) का खण्ड (ञ).**—यह ''मण्डी कृत्यकारी'' की विद्यमान परिभाषा में संशोधन करने हेतु उपबंध करता है और कृषि उपज के भण्डारण को सुकर बनाने के लिए शब्द ''भाण्डागारिक'' का लोप किया जाना प्रस्तावित है.

(दो) **अधिनियम की धारा ३१.**—''भाण्डागारिक'' को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वह भाण्डागार में केवल कृषि-उपज का भण्डारण करता है.

(तीन) **अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (२).**—आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं जैसे तत्काल सकल निपटान, ई-भुगतान, ई-निविदा तथा ई-विपणन इत्यादि के मण्डी समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा उपयोग को सुकर बनाने के लिए, मण्डी समिति निधि के धन तथा अन्य राशियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त करने के लिए उपबंध किया जाना प्रस्तावित है.

(चार) **अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (७).**—यह मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त समस्त धन तथा अन्य राशियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त किए जाने का उपबंध करती है जिससे कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं जैसे तत्काल सकल निपटान, ई-भुगतान तथा निधि का ई-अंतरण संभव हो सके.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १ दिसम्बर, २०१५.

गौरीशंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.